1. भारत के मुख्य न्यायाधीश

- भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए। बोबडे ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमाना को अगले शीर्ष न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है।
- जस्टिस रमना अब 24 अप्रैल से भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं।
- चीफ जस्टिस बोबडे ने सरकार को भेजने के बाद बुधवार को जस्टिस रमना को अपने सिफारिशी पत्र की एक प्रति सौंपी।
- केंद्र ने हाल ही में 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश बोबडे को शीर्ष न्यायिक कार्यालय में संक्रमण प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था।
- 26 अगस्त, 2022 तक जस्टिस रमण CJI होंगे। 17 फरवरी, 2014 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया, जब वे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
- जस्टिस रमना का जन्म 27 अगस्त, 1957 को कृष्णा जिले के पोन्नवरम गाँव में एक कृषि परिवार में हुआ था।

तथय

- भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ भारतीय संघीय न्यायपालिका के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी हैं। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को नामांकित करने की शक्ति प्रदान करता है, और भारत की संसद की सलाह और सहमति से, एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो तब तक सेवा करता है, जब तक कि वे पैंसठ वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते हैं या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है।

2. डबल म्यूटेंट 'कोरोनावायरस संस्करण

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि एक अनोखा "डबल म्यूटेंट" कोरोनावायरस वैरिएंट है - जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया है। हालाँकि, यह अभी भी स्थापित किया जाना है अगर इसमें संक्रामक वृद्धि में या COVID-19 को अधिक गंभीर बनाने में कोई भूमिका है।
- देश भर में 10 प्रयोगशालाओं के एक संघ द्वारा वायरस के नमूनों की जीनोम अनुक्रमण, जीनोमिक्स (INSACOG) पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम कहा जाता है, कम से कम 200 वायरस में एक साथ दो उत्परिवर्तन, E464Q और L452R की उपस्थिति का पता चला महाराष्ट्र से नमूने, साथ ही दिल्ली, पंजाब और गुजरात में मुट्ठी भर।
- प्रति से वायरस में उत्परिवर्तन आश्चर्यजनक नहीं हैं, लेकिन विशिष्ट उत्परिवर्तन जो वायरस को टीके या प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने में मदद करते हैं, या मामलों में या रोग की गंभीरता में स्पाइक से जुड़े होते हैं, रुचि के हैं। जबकि दो उत्परिवर्तन को वैश्विक रूप से SARS-CoV-2 के अन्य वेरिएंट्स में व्यक्तिगत रूप से पहचाना गया है, और टीके की प्रभावकारिता में कमी के साथ-साथ संक्रामकता के साथ जोड़ा गया है, उनके संयुक्त प्रभाव और जैविक निहितार्थ को अभी तक समझा नहीं गया है। आने वाले दिनों में, INSACOG इस वैरिएंट का विवरण GISAID नामक एक वैश्विक रिपॉजिटरी को प्रस्तुत करेगा और, यदि यह योग्यता है, तो इसे "चिंता का विषय" (VOC) के रूप में वर्गीकृत करें।
- भारत ने अभी तक इस पर अध्ययन नहीं किया है कि सीमित प्रयोगशाला परीक्षणों को छोड़कर, वैक्सीन की प्रभावकारिता वेरिएंट से कैसे प्रभावित होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों ने टीकों की कम प्रभावकारिता को दर्शाया है - विशेष रूप से फाइजर, मॉडर्न और नोवैक्स द्वारा - कुछ वेरिएंट को। हालांकि, इसके बावजूद टीके काफी सुरक्षात्मक बने हुए हैं।
- अब तक, केवल तीन वैश्विक वीओसी की पहचान की गई है: यू.के. संस्करण (बी.1.1.7), दक्षिण अफ्रीकी (बी.1.351) और ब्राजील (पी .1) वंश। अब तक, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 10,787 नमूनों में, देश के 18 राज्यों में इन वीओसी के 771 उदाहरणों की पहचान की गई है। GISAID में नया दोहरा संस्करण प्रस्तुत किए जाने के बाद, इसे एक औपचारिक वंश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, और इसका अपना नाम होगा।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

3. ट्यूलिप गार्डन(जम्मू और कश्मीर)

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से **जम्मू और कश्मीर में ज़बरवान रेंज की तलहटी में स्थित ट्यूलिप गार्डन** का दौरा करने और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के गर्म आतिथ्य का आनंद लेने के लिए कहा।
- बागानों के बारे में ट्वीट करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, "जब भी आपको अवसर मिले, जम्मू और कश्मीर की यात्रा करें और सुंदर तुलसी उत्सव का गवाह बनें। ट्यूलिप के अलावा, आप जम्मू और कश्मीर के लोगों के गर्म आतिथ्य का अनुभव करेंगे।
- 25 मार्च जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष है। ज़बरवान पर्वत की तलहटी पर एक राजसी ट्यूलिप गार्डन आगंतुकों के लिए खुल जाएगा। उद्यान में खिलने के 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूल दिखाई देंगे, "श्री मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा।
- ट्यूलिप गार्डन ज़ाबेरवान रेंज की तलहटी में डल झील के अवलोकन के साथ स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यह लगभग 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इस उद्यान को 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था।
- यह उद्यान एक टेढ़ी-मेढ़ी जमीन पर बना है, जिसमें सात छतों से बना है। ट्यूलिप के अलावा, फूलों की कई अन्य प्रजातियां जैसे कि हाइकाइन्थ्स, डैफोडिल्स और रेनकुलस को जोड़ा गया है।
- घाटी में वसंत के मौसम की शुरुआत में आयोजित होने वाला ट्यूलिप उत्सव एक वार्षिक उत्सव है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पर्यटन प्रयासों के तहत बगीचे में फूलों की श्रेणी का प्रदर्शन करना है।

4. संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2021

- 24 मार्च को लोकसभा ने **नेशनल एलायड फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स बिल, 2021 को मंजूरी दे** दी, जो कि संबद्ध स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहता है, देश भर में प्रशिक्षण और योग्यता का मानकीकरण करता है। राज्यसभा ने 16 मार्च को विधेयक पारित किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कानून, जिसे लोकसभा में पार्टी की तर्ज पर द्विदलीय समर्थन मिला, का उद्देश्य सेक्टर की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करना है, और पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
- पैरामेडिक्स और संबद्ध स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा पेशे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका योगदान डॉक्टरों के समान है, यदि अधिक नहीं है। संबद्ध पेशेवरों का समूह बड़ा है और बिल उनकी भूमिकाओं को गरिमा प्रदान करके इस क्षेत्र को विनियमित करने का प्रयास कर रहा है।
- विधेयक संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं की 50 श्रेणियों के लिए एक नियामक संरचना स्थापित करेगा और डॉक्टर केंद्रित होने से लेकर टीम केंद्रित तक के रोगियों के उपचार की कोशिश और बदलाव करेगा।
- विधेयक का उद्देश्य एक वैधानिक निकाय या आयोग की स्थापना करना है जो नीतियों और मानकों को फ्रेम करता है, संस्थानों के बीच सेवा मानकों की एकरूपता प्रदान करने के अलावा, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए पेशेवर आचरण और योग्यता को विनियमित करता है। निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन दो साल के लिए किया जाएगा और वे दो कार्यकाल के लिए त्याग के पात्र होंगे। राज्य सरकारों को आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, 12 सीटें उनके लिए अलग रखी गई हैं, और राज्य स्तरीय आयोगों को भी विधेयक के तहत स्थापित किया जाना है।

ACHIEVERS IAS AC

- विनियमन, प्रशिक्षण, पात्रता और सेवा के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय यार्डस्टिक्स द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता (ILO) कोड के अनुसार कोडित किया गया है। स्वास्थ्य पर स्थायी समिति द्वारा विधेयक को रोक दिया गया था, जिसमें 110 संशोधनों का सुझाव दिया गया था, जिनमें से 102 को विधेयक में शामिल किया गया है, इसके लिए द्विदलीय समर्थन का एक कारण है।

5. योग्यता, कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीबीएसई मूल्यांकन

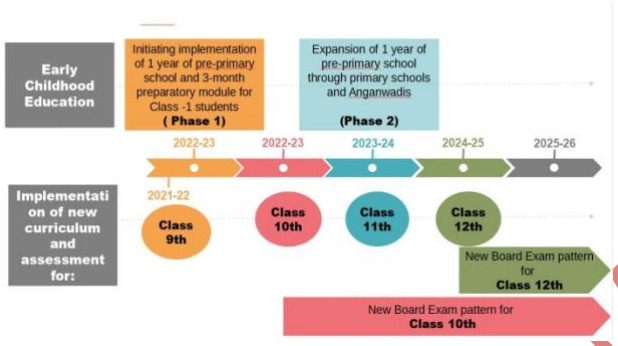

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में कक्षा 6-10 के लिए एक नया मूल्यांकन ढांचा तैयार किया है। नई प्रणाली के तहत, शिक्षकों को प्रश्न पत्र और अन्य मूल्यांकन विधियों को बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो इन विषयों में छात्रों की वास्तविक योग्यता का परीक्षण करते हैं, न कि पाठ को याद करने की उनकी क्षमता के बजाय।
- नए ढांचे को लॉन्च करते हुए, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मूल्यांकन में एक वैश्विक मानक प्राप्त करने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण के साथ गठबंधन किया गया था।
- पहले चरण में, चुनिंदा केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों, चंडीगढ़ के सीबीएसई स्कूलों, और कुछ निजी स्कूलों में रूपरेखा लागू की जाएगी। 2024 तक, इसे देश भर के 25,000 सीबीएसई स्कूलों में रोलआउट किया जाएगा, जिसमें 1.32 लाख शिक्षक और दो करोड़ छात्र होंगे।
- "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की परिकल्पना करती है। यह 21 वीं सदी के लिए छात्रों को तैयार करने का लक्ष्य रखता है और एक शिक्षा के बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देता है, जो रटने की शिक्षा का परीक्षण करता है," बयान में कहा गया है।

6. इंडिया टीबी(tuberculosis) रिपोर्ट

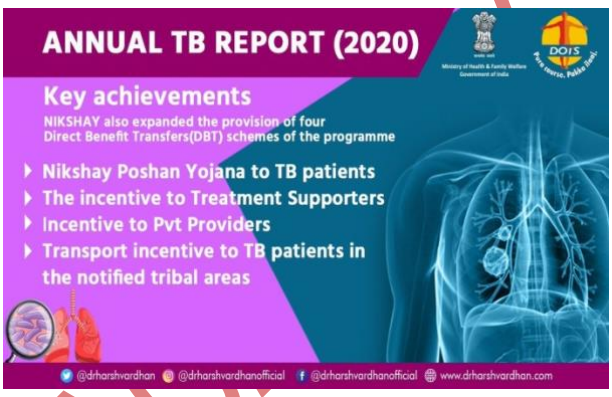

- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 18.05 टीबी की सूचनाएं थीं, जो 2019 में 24% की गिरावट थी, जो महामारी के कारण उत्पन्न हुई व्यवधानों के कारण थी।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी और फरवरी 2020 के बीच, नोटिफिकेशन एक ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र पर था, 2019 में इसी अवधि में 6% अधिक मामले सामने आए।
- लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, अप्रैल और मई में निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में सूचनाएं 38% और 44% तक गिर गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 24.04 लाख टीबी के मामलों में उपचार की सफलता 82% थी, मृत्यु दर 4% थी, 4% रोगियों के इलाज में असफल होने और उपचार में विफलता के बाद उपचार में 3% की कमी आई थी, " रिपोर्ट में कहा गया है
- इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम के लिए अनुमोदित बजटों में 2016-17 में 2016 640 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 3 3,333 करोड़ हो गया है, हालांकि, बजट में 2020-21 में crore 3,110 करोड़ तक की गिरावट आई है।
- रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट किए गए सभी मामलों के 95% से अधिक 2020 में इलाज शुरू किए गए थे और 2019 में रिपोर्ट किए गए रोगियों के लिए उपचार की सफलता दर 82% थी (सार्वजनिक क्षेत्र के रोगियों में 83% और निजी में 79%)।
- रिपोर्ट में कहा गया कि 20,892 (42%) रोगियों का निदान के समय कम एमडीआर-टीबी आहार लिया गया। "यह 2019 से एक महत्वपूर्ण गिरावट है [71% कम एमडीआर-टीबी regimen पर शुरू किए गए]। 2019 में, एमडीआर-टीबी रोगियों के लिए नए ड्रग रेजिमेंट पेश किए गए। 2020 में, बेडाक्विलाइन पर 20,000 से अधिक रोगियों को शुरू किया गया था और 652 रोगियों [6-17 वर्ष की आयु में बाल चिकित्सा

ACHIEVERS IAS ACADEMY

टीबी रोगियों सहित] को डेलमनिड पर शुरू किया गया था, "रिपोर्ट में कहा गया है।

7. भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र

- तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाला छठा अपतटीय गश्ती जहाज भारतीय तटरक्षक जहाज 'वज्र '24मार्च 2021 को चेन्नई में औपचारिक रूप से सेवा में आ गया।
- जहाज के कमीशनिंग को चिह्नित करने के लिए एक समारोह में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने औपचारिक रूप से एक and पट्टिका 'और जहाज के नाम बोर्ड aj वज्र' का अर्थ 'थंडरबोल्ट' चेन्नई सेंट्रल ट्रस्ट में औपचारिक रूप से अनावरण किया।
- जहाज को स्वदेशी रूप से लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। सात अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में छठा, वज्र अत्यधिक परिष्कृत नेविगेशन और संचार प्रणालियों के साथ सुसज्जित है।
- जहाज में मुख्य हथियार के रूप में 30 मिमी की बंदूक होती है और दो एफसीएस नियंत्रित 12.7 मिमी एसआरसीजी (स्थिर रिमोट कंट्रोल गन) से लैस होती है जो कि लड़ने की दक्षता में वृद्धि के लिए होती है।
- पोत की हाईटेक विशेषताओं में से कुछ में शामिल हैं - एक एकीकृत पुल प्रणाली, उच्च शक्ति बाहरी लड़ाई प्रणाली, धनुष थ्रस्टर और स्वचालित बिजली प्रबंधन प्रणाली।
- जहाज को रात की उड़ान क्षमताओं के साथ एक जुड़वां इंजन वाले हेलीकॉप्टर और चार उच्च गति वाली नावों, दो कठोर पतवार वाली नावों को खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त के लिए ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- समुद्र में तेल फैलाने के लिए एक प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण जहाज में फिट किया गया है, जो जुड़वां MTU 8000 श्रृंखला इंजन द्वारा संचालित है, जो 26 समुद्री मील की उच्च गति और 5,000 समुद्री मील की दूरी पर धीरज हासिल करने में सक्षम है।
- उप महानिरीक्षक एलेक्स थॉमस जहाज के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जिसमें 14 अधिकारी और 88 पुरुष होंगे। जहाज तूतिकोरिन पर आधारित होगा जो तटवर्ती पूर्वी क्षेत्र के परिचालन नियंत्रण के तहत होगा।
- COVID-19 महामारी को देखते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करते हुए कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया था।

8. ISSF विश्व कप: 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता !

- भारत ने बुधवार को नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप 2021 में फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता।
- चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता जबकि हमवतन राही सरनोबत ने रजत और मनु भाकर ने राजधानी में डॉ। करणी सिंह शूटिंग रेंज में कांस्य पदक जीता।
- पूर्व एशियाई और सीडब्ल्यूजी स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा द्वारा प्रशिक्षित चिंकी ने भारत की कुल मिलाकर 9 वीं स्वर्ण पदक जोड़ी जबकि एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता राही सरनोबत ने राष्ट्र के लिए 5 वां रजत पदक जीता।
- भारत शूटिंग विश्व कप में अब तक 19 पदकों के साथ पदक जीतने का नेतृत्व कर रहा है - 9 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य।
- इससे पहले, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में एक अंक से कम जीतकर भारत की ताल में इजाफा किया।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

- ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने हंगरी के दूसरे स्थान के इस्तवान पेनी को पिप करने के लिए कुल 462.5 अंक बनाए और डॉ। करणी सिंह शूटिंग रेंज में पोडियम पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। डेनमार्क के स्टीफन ओल्सेन ने 450.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता।
- फाइनल में अन्य भारतीय, अनुभवी संजीव राजपूत और नीरज कुमार क्रमशः 6 वें और 8 वें स्थान पर रहे।

9. पीएफ थ्रेशोल्ड लिमिट टैक्स-फ्री इंटरेस्ट के लिए 5 लाख रुपये !

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में प्रस्तावित 2.5 लाख रुपये के मुकाबले निर्दिष्ट मामलों में कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज पर कर छूट की सीमा 5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी।
- 2021-22 के अपने बजट में, सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित कर-मुक्त ब्याज को एक वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक पहुंचाया, जिससे उच्च अधिशेषियों को उनके अधिशेष को पार करने से रोकने का प्रयास किया गया। माना जाता है कि आम आदमी रिटायरमेंट फंड है।
- लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए, मंत्री ने कहा कि कर-मुक्त सीमा में अब अधिकतम 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष संशोधन किया जा रहा है।
- यह छूट, हालांकि, इस शर्त के अधीन है कि 5 लाख रुपये तक के योगदान में मूल वेतन के 12 प्रतिशत तक वैधानिक सीमा से परे नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है।
- नया प्रावधान एक अप्रैल से लागू होगा।
- उन्होंने स्पष्ट किया कि 2.5 लाख रुपये की सीमा 92-93 प्रतिशत लोगों को कवर कर रही है, जो ग्राहक हैं और वे इस योजना के तहत कर मुक्त होने के लिए आश्वस्त ब्याज के हकदार हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के छह करोड़ से अधिक ग्राहक हैं।
- वित्त विधेयक को बाद में निचले सदन द्वारा ध्वनिमत से 127 आधिकारिक संशोधनों के साथ पारित किया गया।
- सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी की बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी शामिल है।
- यह राशि रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपये से कम है, जिसे चालू वित्त वर्ष में सीपीएसई विनिवेश से उठाया जाना था
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये में से, 1 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने से आने हैं। 75,000 करोड़ रुपये सीपीएसई विनिवेश प्राप्तियों के रूप में आएंगे।
- उन्होंने फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए एक सदस्य की आलोचना करते हुए कहा कि सांसद को थिंक टैंक के साथ भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को उठाना चाहिए।

10. लोकसभा ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 पारित किया !

- बच्चों की सुरक्षा और गोद लेने के प्रावधानों को मजबूत करने के उद्देश्य से लोकसभा ने बुधवार को किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया।
- महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2021 उन कई चिंताओं

ACHIEVERS IAS ACADEMY

को दूर करता है जिन्हें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा पारित किए गए विधेयक के पहले संस्करण की जांच करते हुए किया गया था। 2015 में।

- सुश्री ईरानी ने कहा कि संशोधित कानून ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को डीएम और एडिशनल डीएम को सशक्त बनाने और बच्चों की देखभाल और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर अधिक निर्णय लेने के साथ बच्चों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए एक "समन्वय अधिकारी" बनाया।
- विधेयक में उन अपराधों को भी शामिल किया गया था, जिनमें अधिकतम सजा सात साल से अधिक के कारावास की थी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कोई भी न्यूनतम सजा या सात साल से कम की सजा नहीं दी गई थी। गंभीर अपराधों में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता के तहत सजा तीन से सात साल के बीच कारावास है।
- विधेयक बाल कल्याण समिति का सदस्य होने के लिए न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति को तब तक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सात साल तक बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुआ था या बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र या में डिग्री के साथ पेशेवर अभ्यास कर रहा था। मानव विकास।
- विधेयक ने समिति के एक सदस्य के कार्यकाल को समाप्त करने की भी मांग की, अगर वे तीन महीने तक बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन महीने तक बाल कल्याण समिति की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए या वे तीन-चौथाई से कम बैठक में शामिल नहीं हो पाए। साल।

ACHIEVERS IAS ACADEMY